



SATYADHEESH

सत्याधीश

यूपीएससी दैनिक विस्तृत नोट्स

करेंट अफेयर्स • 19 अगस्त 2026

44

नोट्स

4

खबरें जोड़ी गईं

GS1 • 1

GS2 • 28

GS3 • 15

पेपर मिश्रण

विषय सूची

सभी नोट्स, पेपर के अनुसार

GS1

इतिहास • समाज • भूगोल

1 नोट्स

भारतीय समाज

1

GS2

राज्यव्यवस्था • शासन • सामाजिक न्याय • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

28 नोट्स

राज्यव्यवस्था एवं संविधान

9

शासन

7

सामाजिक न्याय

4

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

8

GS3

अर्थव्यवस्था • विज्ञान-तकनीक • पर्यावरण • सुरक्षा

15 नोट्स

अर्थव्यवस्था

8

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

2

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

3

आपदा प्रबंधन

1

आंतरिक सुरक्षा

1

हर नोट में

चर्चा में क्यों → याद रखने योग्य तथ्य → कीवर्ड के साथ मेन्स प्रश्न। एक ही खबर की रिपोर्टें जोड़ दी गई हैं।

समय कम है?

5 पेज के सार में सबसे ज़रूरी खबरें और अभ्यास प्रश्न हैं।

भारतीय समाज

1

URBANISATION

P

M

19 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/107909

दिल्ली में सिर्फ 5% बिल्डिंग्स को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, 71 स्टेशनों की कमी

चर्चा में क्यों एक रिपोर्ट दिल्ली में अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे की गंभीर कमी को रेखांकित करती है, जहाँ केवल 5% इमारतों को प्रमाणित किया गया है, जो तृतीय-पक्ष प्रमाणन (third-party certification) और बुनियादी ढांचे के विस्तार की ओर बदलाव की आवश्यकता को दर्शाती है।

- तथ्य | वर्तमान में दिल्ली में केवल 5% इमारतों के पास Occupancy Certificates हैं।
- तथ्य | दिल्ली को 120 फायर स्टेशनों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में यह 71 के साथ संचालित हो रहा है।
- विज्ञान | प्रस्तावित सुरक्षा उपायों में उच्च-जोखिम वाली इमारतों में अनिवार्य स्प्रिंकलर और स्मोक डिटेक्टर शामिल हैं।

मेन्स प्रश्न महानगरीय शहरों में शहरी अग्नि सुरक्षा प्रबंधन के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और बुनियादी ढांचे एवं विनियामक अनुपालन में सुधार के लिए उचित उपाय सुझाइए। चर्चा कीजिए।

राज्यवस्था एवं संविधान

9

STATUTORY, REGULATORY & QUASI-JUDICIAL BODIES

P

M

19 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/108339

NMC ने डॉक्टरों के लिए सिंगल ID और हर 5 साल में रिन्यूअल का प्रस्ताव दिया

चर्चा में क्यों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने भारत भर में निर्बाध अभ्यास की सुविधा प्रदान करने हेतु चिकित्सकों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली बनाने के लिए एक मसौदा संशोधन प्रस्तावित किया है।

संस्था	NMC: National Medical Commission भारत में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था है।
तथ्य	लाइसेंस नवीनीकरण: सक्रिय स्थिति बनाए रखने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में अनिवार्य नवीनीकरण का प्रस्ताव।
संस्था	एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड: चिकित्सा पंजीकरण के संबंध में अपीलों की सुनवाई के लिए नामित निकाय।

मेन्स प्रश्न भारत में चिकित्सा चिकित्सकों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली स्वास्थ्य सेवा वितरण और व्यावसायिक जवाबदेही को किस प्रकार बेहतर बना सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।

JUDICIARY & LANDMARK JUDGMENTS

P

M

19 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/107837

सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करने के लिए Article 142 का इस्तेमाल करने पर सहमति दी

चर्चा में क्यों उच्चतम न्यायालय ने NEET-UG के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के विरुद्ध दर्ज FIR को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया, जो असाधारण मामलों में न्याय सुनिश्चित करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति को रेखांकित करता है।

संविधान	अनुच्छेद 142: सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्ली या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है।
संस्था	भारत का सर्वोच्च न्यायालय: देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जो मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।
तथ्य	Solicitor General द्वारा प्रदर्शनकारियों के बीच आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2,873 व्यक्तियों की पहचान की गई।

मेन्स प्रश्न अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण शक्तियों के दायरे और सीमाओं का विश्लेषण कीजिए, विशेष रूप से विरोध के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के बीच संतुलन स्थापित करने के संदर्भ में। चर्चा कीजिए।

FEDERALISM & CENTRE-STATE RELATIONS

P

19 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/108493

दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और संघीय समन्वय पर चर्चा करने के लिए दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक आयोजित की गई

चर्चा में क्यों दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और संघीय समन्वय पर चर्चा करने के लिए दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक आयोजित की गई।

संस्था	क्षेत्रीय परिषद (Zonal Councils) केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की सुविधा के लिए स्थापित वैधानिक निकाय हैं।
संस्था	केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) के कामकाज की देखरेख करता है।
तथ्य	दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (Southern Zonal Council) में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य शामिल हैं।

मेन्स प्रश्न भारत में सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान में क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

तमिल थाई वझु प्राथमिकता पर तमिलनाडु के फैसले को मद्रास हाई कोर्ट का समर्थन

चर्चा में क्यों मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य स्वायत्तता पर MHA के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए, आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान राज्य के गीत 'तमिल थाई वझु' को प्राथमिकता देने के तमिलनाडु के अधिकार को बरकरार रखा है।

संविधान	अनुच्छेद 29(1) अल्पसंख्यकों के हितों और उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकार की रक्षा करता है।
तथ्य	तमिल थाई वझु (Tamil Thai Vazhthu) तमिलनाडु का आधिकारिक राज्य गीत है।
संस्था	गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्य गीतों के क्रम के संबंध में परिपत्र जारी किया।

मेन्स प्रश्न भारतीय संघीय संरचना के अंतर्गत राष्ट्रीय एकरूपता बनाए रखने में केंद्र की भूमिका और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के राज्यों के अधिकारों के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।

आंध्र प्रदेश में 18 साल बाद फिर शुरू होंगे सीधे मेयर चुनाव

चर्चा में क्यों आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 18 वर्षों के अंतराल के पश्चात महापौरों और अध्यक्षों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव बहाल करने हेतु 'नगरपालिका कानून (चौथा संशोधन) विधेयक, 2026' पारित किया है।

अधि नियम	आंध्र प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को Municipal Corporations Act, 1955 और Municipalities Act, 1965 द्वारा शासित किया जाता है।
तथ्य	आंध्र प्रदेश में 6 अगस्त, 2005 से महापौरों और अध्यक्षों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव निलंबित कर दिए गए हैं।
तथ्य	नया संशोधन महापौर और अध्यक्ष के पदों के लिए पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल निर्धारित करता है।

मेन्स प्रश्न भारत में शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुखों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की बहाली किस प्रकार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ कर सकती है और शहरी शासन में सुधार ला सकती है, चर्चा कीजिए।

सुप्रीम कोर्ट की ओडिशा को चेतावनी: दारा सिंह की रिमिशन याचिका पर कार्रवाई करें वरना हस्तक्षेप झेलें

चर्चा में क्यों उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा सरकार को 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेनिस की हत्या के दोषी, दारा सिंह की सजा माफी की याचिका पर निर्णय में विलंब न करने की चेतावनी दी है।

संस्था	भारत का सर्वोच्च न्यायालय: न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) की शक्ति के साथ भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय।
तथ्य	दारा सिंह: 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेनिस की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया।
स्थान	ओडिशा: जेल रिमिशन (prison remission) नियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।

मेन्स प्रश्न कारागार सुधार और क्षमा नीतियों के प्रशासन में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

महाराष्ट्र सरकार ने 14 अगस्त से फडणवीस को मंत्रियों के फैसले ओवरराइड करने की पावर दी

चर्चा में क्यों महाराष्ट्र सरकार ने 'महाराष्ट्र सरकार के कार्य संचालन नियम, 2026' (Maharashtra Government Rules of Business, 2026) अधिसूचित किए हैं, जो मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्रियों के निर्णयों को ओवरराइड करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

तथ्य	महाराष्ट्र सरकार के व्यवसाय नियम, 2026: कार्यकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नए नियम।
संस्था	वित्त विभाग: वित्तीय निहितार्थ वाले निर्णयों के लिए सहमति प्रदान करना अनिवार्य है।
पद	मुख्यमंत्री: नए नियमों के तहत कैबिनेट के निर्णयों को ओवरराइड करने की शक्ति रखते हैं।

मेन्स प्रश्न मुख्यमंत्री कार्यालय के भीतर कार्यकारी शक्तियों के केंद्रीकरण का गठबंधन सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिवशंकरप्पा एस. सहकार को फिर से KPSC चेयरमैन नियुक्त किया

चर्चा में क्यों कर्नाटक उच्च न्यायालय ने KPSC के अध्यक्ष के निलंबन को रद्द कर दिया है और इस निर्णय में इस बात पर बल दिया है कि राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना एक संवैधानिक आवश्यकता है।

संस्था	KPSC: Karnataka Public Service Commission एक राज्य-स्तरीय निकाय है जो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए उत्तरदायी है।
संविधान	अनुच्छेद 165: यह प्रावधान करता है कि राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) से संबंधित मामलों में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा।
पद	राज्यपाल: भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

मेन्स प्रश्न राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के राज्यपाल के दायित्व के संवैधानिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।

महाराष्ट्र वोटर लिस्ट के पहले फेज में 2.07 करोड़ वोटर्स बाहर

चर्चा में क्यों महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 के दौरान प्रारूप मतदाता सूची से 2.07 करोड़ मतदाताओं को बाहर करने की घोषणा की है।

संस्था	राज्य में चुनावी नामावली (electoral rolls) तैयार करने और उनके रखरखाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) प्राथमिक प्राधिकारी होता है।
तथ्य	Special Intensive Revision (SIR) 2026 का उद्देश्य 'ASDD' श्रेणियों: Permanently Shifted, Absent/Not Found, Deceased और Duplicate प्रविष्टियों को हटाना है।
तथ्य	महाराष्ट्र के लिए अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाली है।

मेन्स प्रश्न लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने और चुनावी धोखाधड़ी को रोकने में निर्वाचन नामा (voter list) के समय-समय पर संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।

शासन

7

तमिलनाडु के PWD मंत्री Aadhav Arjuna की PWD आधुनिकीकरण योजना

चर्चा में क्यों तमिलनाडु के लोक निर्माण मंत्री ने PWD के लिए एक आधुनिकीकरण योजना की घोषणा की है, जिसमें AI-सक्षम प्रणालियों, वर्टिकल डेवलपमेंट और एक नए बुनियादी ढांचा निगम को शामिल किया गया है।

तथ्य	तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन: बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए नई संस्था, जिसे ₹1 करोड़ की प्रारंभिक फंडिंग दी गई है।
विज्ञान	AI-enabled Building Management System: IIT के सहयोग से राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के लिए नियोजित।
तथ्य	FSI (Floor Space Index): कुल निर्मित फर्श क्षेत्र और भूखंड क्षेत्र के अनुपात को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक माप।

मेन्स प्रश्न भारत में राज्य स्तरीय लोक निर्माण विभागों की दक्षता को बढ़ाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का एकीकरण और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, चर्चा कीजिए।

KERC ने बिजली का ड्राफ्ट पब्लिश किया

चर्चा में क्यों कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (KERC) ने उपभोक्ता पारदर्शिता बढ़ाने और कनेक्शन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से विद्युत आपूर्ति विनियम (ESR) 2026 का एक मसौदा जारी किया है।

संस्था	KERC: कर्नाटक में विद्युत क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय।
तथ्य	ESR 2026: बिजली कटौती की आवृत्ति और अवधि के अनिवार्य प्रकटीकरण की आवश्यकता वाले मसौदा नियम।
तथ्य	स्व-प्रमाणन (Self-certification): नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु एक प्रस्तावित तंत्र।

मेन्स प्रश्न भारत के विद्युत क्षेत्र में विनियामक सुधार किस प्रकार उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ कर सकते हैं और व्यापार करने की सुगमता (ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस) में सुधार कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।

मद्रास हाई कोर्ट, जिसमें जस्टिस जी.आर. शामिल हैं

चर्चा में क्यों मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को बच्चों से संबंधित आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में मौजूद प्रणालीगत कमियों को दूर करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

संस्था	मद्रास उच्च न्यायालय: तमिलनाडु राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
तथ्य	सरकार को समिति की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चार महीने की समय-सीमा दी गई है।
विज्ञान	SOPs (Standard Operating Procedures) प्रशासनिक और कानूनी कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित प्रोटोकॉल हैं।

मेन्स प्रश्न भारत में बाल न्याय प्रणाली के कार्यान्वयन में निहित प्रणालीगत चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और एक बाल-केंद्रित कानूनी ढांचा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

हाउसिंग और रेवेन्यू मंत्री Ponguleti Srinivas Reddy ने सीमेंट इंडस्ट्रीज से सप्लाई की मांग की

चर्चा में क्यों आंध्र प्रदेश के आवास एवं राजस्व मंत्री ने निर्माण लागत में हो रही वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सीमेंट उद्योगों से 'इन्दिरम्मा हाउस' परियोजना के लिए रियायती दर पर सीमेंट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

तथ्य	इन्दिरम्मा हाउस प्रोजेक्ट: हैदराबाद के बाहर चरण 1 के तहत 4.5 लाख घरों को मंजूरी दी गई।
तथ्य	इन्दिरम्मा हाउस प्रोजेक्ट: चरण 2 के तहत अतिरिक्त 2.5 लाख घरों को मंजूरी दी जाएगी।
तथ्य	प्रति घर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी: ₹5 लाख।

मेन्स प्रश्न निर्माण सामग्री की बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच, राज्य सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर आवास योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

छात्रों के विरोध के बाद झारखंड ने 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कीं

चर्चा में क्यों झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, जो सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं में प्रणालीगत समस्याओं और पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

संस्था	JPSC: Jharkhand Public Service Commission सिविल सेवकों की भर्ती के लिए राज्य स्तरीय निकाय है।
संस्था	TDPL: झारखंड शिक्षक भर्ती बोर्ड (पूर्व में शिक्षक तैनाती और प्लेसमेंट बोर्ड के रूप में जाना जाता था)।
तथ्य	यह रद्दीकरण 2014 से आयोजित परीक्षाओं को कवर करता है।

मेन्स प्रश्न राज्य लोक सेवा आयोगों की भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए।

NTA Overhaul: जोशी ने नेशनल एग्जाम्स के लिए कड़ी सुरक्षा और फोर-टियर चेक के आदेश दिए

चर्चा में क्यों केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बार-बार होने वाली परीक्षा धांधली के बाद जनता का विश्वास बहाल करने के लिए NTA को चार-स्तरीय जाँच प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है।

संस्था	NTA (National Testing Agency): एक स्वायत्त निकाय जो प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
पद	प्रह्लाद जोशी: केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार।
तथ्य	NTA त्रुटियों और रिसावों को कम करने के लिए चार-स्तरीय जाँच प्रणाली (four-tier checking system) लागू कर रहा है।
संस्था	CISF (Central Industrial Security Force): स्थानांतरित NTA कार्यालयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी।

मेन्स प्रश्न भारत में उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय परीक्षाओं की अखंडता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा कदाचार को रोकने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

तमिलनाडु में ₹500 करोड़ सालाना के बजट के साथ चीफ मिनिस्टर रोड सेफ्टी मिशन शुरू होगा

चर्चा में क्यों सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली उच्च मृत्यु दर को संबोधित करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने ₹500 करोड़ के वार्षिक बजट के साथ 'मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा मिशन' की घोषणा की है।

तथ्य	मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा मिशन का बजट: ₹500 करोड़ वार्षिक।
विज्ञान	ANPR: गति और पंजीकरण की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले Automatic Number Plate Recognition कैमरे।
स्थान	तमिलनाडु: उच्च सड़क दुर्घटना दर वाला राज्य, जो इस मिशन का कारण बना।

मेन्स प्रश्न भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर को कम करने में तकनीकी हस्तक्षेप और आपातकालीन चिकित्सा बुनियादी ढांचे की भूमिका पर चर्चा कीजिए। राज्य केरल जैसे सफल मॉडलों को अन्य राज्यों में कैसे प्रतिरूपित किया जा सकता है? चर्चा कीजिए।

सामाजिक न्याय

4

कम ही लोग जानते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी थी

चर्चा में क्यों पैलिएटिव केयर (palliative care) के लिए सार्वजनिक जागरूकता और बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण, पैसिव यूथेनेसिया (passive euthanasia) और 'लिविंग विल्स' (living wills) पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के 2018 के निर्णय को चर्चा में लाया जा रहा है।

संस्था	AIIMS: नई दिल्ली में एक प्रमुख सार्वजनिक चिकित्सा अनुसंधान और तृतीयक देखभाल (tertiary care) अस्पताल।
तथ्य	पैसिव यूथेनेसिया (Passive Euthanasia): किसी मरीज को प्राकृतिक रूप से मृत्यु की ओर जाने देने के लिए जीवन-रक्षक उपचार (जैसे वेंटिलेटर) को वापस लेना।
तथ्य	लिविंग विल (Living Will): एक व्यक्ति द्वारा किया गया कानूनी घोषणापत्र जिसमें वह यह निर्दिष्ट करता है कि लाइलाज बीमारी की स्थिति में वह कौन से चिकित्सा उपचार चाहता है या नहीं चाहता है।

मेन्स प्रश्न भारत में 'लिविंग विल' (Living Will) और पैसिव इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) से जुड़े नैतिक और कानूनी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। राज्य उपशामक देखभाल (Palliative Care) के बुनियादी ढांचे में कैसे सुधार कर सकता है? विश्लेषण कीजिए।

NEET-UG लीक पर सुप्रीम कोर्ट की NTA से कड़ी पूछताछ, Nilekani टास्क फोर्स पर उठाए सवाल

चर्चा में क्यों उच्चतम न्यायालय ने NEET-UG प्रश्नपत्रों के लीक होने और विभिन्न कार्य बल (task forces) के बीच सुधारों के कार्यान्वयन में निरंतरता के अभाव के संबंध में National Testing Agency (NTA) से प्रश्न पूछे हैं।

संस्था	NTA: National Testing Agency एक स्वायत्त निकाय है जो NEET और JEE जैसी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
पद	नंदन निलेकणी: UIDAI के पूर्व अध्यक्ष और परीक्षा सुधार के लिए टास्क फोर्स के वर्तमान प्रमुख।
तथ्य	SUPREME COURT ने NEET-UG परीक्षा के संबंध में 19 अगस्त, 2026 को अपनी टिप्पणियाँ दीं।

मेन्स प्रश्न भारत में बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और तकनीकी सुधारों को संस्थागत बनाने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने UGC-NET रिजल्ट पर रोक की याचिका खारिज की, रीटेस्ट के आदेश दिए

चर्चा में क्यों दिल्ली उच्च न्यायालय ने UGC-NET परिणामों पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने कथित प्रश्नपत्रों के रिसाव के कारण विशिष्ट विषयों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया।

संस्था	UGC-NET: इसे University Grants Commission द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु आयोजित किया जाता है।
तथ्य	समाजशास्त्र, अंग्रेजी और वाणिज्य विषयों के पेपर के लिए सितंबर 2026 में पुनः परीक्षा (Retests) निर्धारित की गई है।
पद	Solicitor General: भारत सरकार के सर्वोच्च पदस्थ विधि अधिकारी।

मेन्स प्रश्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और प्रश्नपत्रों की चोरी एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियों को रोकने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।

तमिलनाडु में तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव बढ़ाकर 365 दिन की हुई

चर्चा में क्यों तमिलनाडु सरकार ने अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 365 दिन करने की महत्वपूर्ण घोषणा की है।

तथ्य	तमिलनाडु ने तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया है।
पद	मंत्री D Sarathkumar ने कल्याणकारी उपाय की घोषणा की।

मेन्स प्रश्न भारत में राज्य-नेतृत्व वाली मातृत्व अवकाश नीतियों के महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण में योगदान का विश्लेषण कीजिए।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

8

Syria ने UN जांच के सामने दिखाया भारी मात्रा में न्यूक्लियर मटेरियल, IAEA ने की तारीफ

चर्चा में क्यों संयुक्त राष्ट्र की जांच के दौरान सीरिया ने IAEA को परमाणु सामग्री के कई टन का खुलासा किया, जो परमाणु अप्रसार में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की भूमिका को रेखांकित करता है।

संस्था	IAEA: International Atomic Energy Agency, संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ढांचे के भीतर एक स्वायत्त संगठन।
विज्ञान	परमाणु सुरक्षा (Nuclear Safeguards): वे उपाय जो यह सत्यापित करते हैं कि परमाणु सामग्री का उपयोग हथियारों के लिए नहीं किया जा रहा है।
तथ्य	सीरिया ने UN जांच को बशीर अल-असद युग से संबंधित सामग्री का खुलासा किया।

मेन्स प्रश्न वैश्विक परमाणु अप्रसार में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की भूमिका के महत्व और संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में परमाणु सामग्रियों की निगरानी से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

दिल्ली मीटिंग में BRICS ने EU के कार्बन प्लान को "एकतरफा और भेदभावपूर्ण" बताया

चर्चा में क्यों नई दिल्ली में आयोजित 12वें पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में BRICS देशों ने सामूहिक रूप से EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) का विरोध किया और व्यापारिक निष्पक्षता एवं जलवायु वित्त पर अपनी चिंताओं को रेखांकित किया।

अंत.	संगठन	BRICS: एक अंतर-सरकारी संगठन जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (तथा नए सदस्य) शामिल हैं।
विज्ञान		CBAM: EU में आयातित कार्बन-गहन उत्पादों पर एक कार्बन टैक्स।
तथ्य		यह बैठक BRICS का 12वां पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन थी।

मेन्स प्रश्न यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे एकपक्षीय व्यापार उपायों का ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों के जलवायु लक्ष्यों और आर्थिक हितों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।

जम्मू-कश्मीर दौरे के बाद भारत के लिए ट्रैवल एडवाइजरी पर US एंबेसडर बदल सकते हैं अपना फैसला

चर्चा में क्यों अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर की यात्रा के पश्चात जम्मू और कश्मीर के लिए 'लेवल 4' के यात्रा परामर्श (travel advisory) में संभावित संशोधन का संकेत दिया है।

तथ्य	जम्मू और कश्मीर के लिए US यात्रा परामर्श वर्तमान में लेवल 4 (Do Not Travel) पर है।
पद	Sergio Gor वर्तमान में भारत में अमेरिकी राजदूत हैं।
स्थान	श्रीनगर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है।

मेन्स प्रश्न जम्मू और कश्मीर में कूटनीतिक जुझाव और सुरक्षा सुधार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।

रामल्लाह talks में भारत के MEA Secretary ने टू-स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन दोहराया

चर्चा में क्यों विदेश मंत्रालय (MEA) की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फिलिस्तीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की, जिसमें दो-राज्य समाधान (two-state solution) पर भारत के रुख की पुष्टि की गई और गाजा की मानवीय स्थिति पर चर्चा की गई।

स्थान	रामल्लाह: फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण (Palestinian National Authority) का प्रशासनिक केंद्र और डी फैक्टो (de facto) राजधानी।
तथ्य	भारत का आधिकारिक रुख: इज़राइली-फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए दो-राज्य समाधान (two-state solution) का समर्थन।
पद	श्रीप्रिया रंगनाथन: विदेश मंत्रालय (MEA) में सचिव।

मेन्स प्रश्न इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के मध्यस्थता में भारत की रणनीतिक भूमिका और मध्य पूर्व में इसके 'दो-राष्ट्र समाधान' (Two-State Solution) के रुख के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

भारत के रिजिजू ने चीन के घुसपैठ के दावों को गलत बताया

चर्चा में क्यों केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ के चीनी दावों को खारिज कर दिया और सीमा पर स्पष्ट सीमांकन के अभाव को रेखांकित किया।

स्थान	अरुणाचल प्रदेश: पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य जो चीन की सीमा से सटा हुआ है।
संस्था	ITBP: Indo-Tibetan Border Police, LAC की सुरक्षा के लिए प्राथमिक बल।
तथ्य	अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच की सीमा स्पष्ट रूप से demarcated नहीं है।

मेन्स प्रश्न चीन के साथ स्पष्ट रूप से निर्धारित सीमा के अभाव से उत्पन्न चुनौतियों और सीमा प्रबंधन में बुनियादी ढाँचे के विकास के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

केरल हाई कोर्ट ने पेरियार टाइगर रिजर्व में फिल्म की शूटिंग रोक दी, फिल्ममेकर की याचिका खारिज

चर्चा में क्यों केरल उच्च न्यायालय ने पेरियार टाइगर रिजर्व में एक व्यावसायिक फिल्म की शूटिंग पर रोक लगा दी है, जो वन्यजीव अभयारण्यों को व्यावसायिक शोषण के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्थान	पेरियार टाइगर रिजर्व केरल के पश्चिमी घाट में स्थित है।
तथ्य	न्यायालय ने 19 अगस्त, 2026 को याचिका को खारिज कर दिया।
संस्था	त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने प्रारंभ में वन अधिकारियों की स्वीकृति के अधीन अनुमति प्रदान की थी।

मेन्स प्रश्न भारत में रचनात्मक उद्योगों के विकास और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

UNHCR, SICCI और Ethiraj

चर्चा में क्यों UNHCR, SICCI और एथिरज कॉलेज ने तमिलनाडु में श्रीलंकाई शरणार्थियों की आत्मनिर्भरता हेतु शिक्षा और अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

संस्था	UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees, एक UN एजेंसी जिसे शरणार्थियों की सुरक्षा का अधिदेश प्राप्त है।
स्थान	तमिलनाडु: इस MoU में शरणार्थी आत्मनिर्भरता पहल के लिए प्राथमिक केंद्र राज्य।
तथ्य	यह पहल शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से 'शरणार्थी आत्मनिर्भरता' पर केंद्रित है।

मेन्स प्रश्न भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में शरणार्थियों के एकीकरण से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए तथा इस प्रक्रिया में नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय निकायों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

अमेरिकी व्हाइट हाउस ने एक रिपोर्ट जारी कर भारत और 39 अन्य देशों पर पारगमन (transshipment) के माध्यम से चीनी टैरिफ चोरी (tariff evasion) को सुगम बनाने का आरोप लगाया है, जो भारत के व्यापारिक संबंधों के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है

चर्चा में क्यों अमेरिकी व्हाइट हाउस ने एक रिपोर्ट जारी कर भारत और 39 अन्य देशों पर पारगमन (transshipment) के माध्यम से चीनी टैरिफ चोरी (tariff evasion) को सुगम बनाने का आरोप लगाया है, जो भारत के व्यापारिक संबंधों के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है।

तथ्य | अमेरिका ने भारत और 39 अन्य देशों पर चीनी टैरिफ चोरी (tariff evasion) को सक्षम बनाने का आरोप लगाया है।

तथ्य | भारत ने पूर्व में व्यापारिक दबाव के जवाब में मोटरसाइकिल और झींगा आहार (shrimp feed) पर टैरिफ कम किए हैं।

तथ्य | यह रिपोर्ट White House द्वारा 19 अगस्त, 2026 को प्रकाशित की गई थी।

मेन्स प्रश्न चीन पर अपनी विनिर्माण निर्भरता और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक व्यापार संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

अर्थव्यवस्था

8

MONETARY POLICY, RBI & BANKING

P

M

19 अगस्त • NDTV • satyadheesh.in/news/108111

RBI ने फास्ट फ्लोटिंग-रेट लोन का प्रस्ताव दिया, हर 3 महीने में बदलेंगे इंटररेस्ट रेट

चर्चा में क्यों RBI ने ब्याज दर संचरण (interest rate transmission) को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से फ्लोटिंग-रेट होम लोन के रिसेट चक्र को वार्षिक से घटाकर प्रति तीन माह करने का एक मौसमी प्रस्तावित किया है।

संस्था	RBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
तथ्य	प्रस्तावित पुनः निर्धारण आवृत्ति: प्रत्येक तीन महीने (पूर्व में वार्षिक)।
तथ्य	अनुप्रयोज्यता: विशेष रूप से गृह ऋण (home loans) को लक्षित करता है; व्यक्तिगत और ऑटो ऋण (personal and auto loans) को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
तथ्य	प्रवासन की समय सीमा: मौजूदा उधारकर्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 1 अप्रैल, 2029 तक माइग्रेट करना होगा।

मेन्स प्रश्न भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गृह ऋणों के लिए ब्याज दर पुनः निर्धारण चक्र (interest rate reset cycle) को छोटा करने के प्रस्ताव का भारत में अधिक कुशल मौद्रिक नीति संचरण (monetary policy transmission) में योगदान कैसे होता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

INFRASTRUCTURE (ENERGY, PORTS, ROADS, RAILWAYS)

P

3 रिपोर्टें जोड़ी गईं

19 अगस्त • NDTV • satyadheesh.in/news/108594

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को Union Cabinet की मंजूरी की घोषणा की

चर्चा में क्यों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार में प्रमुख रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं और चार-लेन राजमार्ग विस्तार को स्वीकृति प्रदान की है।

तथ्य	रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं की कुल लागत: Rs 9,450 करोड़।
स्थान	NH-22 का अपग्रेडेशन बिहार में मुजफ्फरपुर-सितामढ़ी-सोनबरसा खंड को कवर करता है।
तथ्य	NH-22 के उन्नयन की लागत: Rs 3,590.73 करोड़।
स्थान	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

मेन्स प्रश्न भारत में लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाने के 'गति शक्ति' विजन में बहु-मोडल परिवहन बुनियादी ढांचे का विस्तार किस प्रकार योगदान देता है, चर्चा कीजिए।

INFRASTRUCTURE (ENERGY, PORTS, ROADS, RAILWAYS)

P

19 अगस्त • NDTV • satyadheesh.in/news/108226

Mumbai 3.0 में Navi Mumbai एयरपोर्ट के पास \$12 billion के निवेश से बनेगा नया अर्बन सेंटर

चर्चा में क्यों MMRDA ने मुंबई महानगर क्षेत्र में भूमि दबाव और बुनियादी ढांचे के तनाव को कम करने के उद्देश्य से नवी मुंबई एयरपोर्ट के निकट 'मुंबई 3.0' नामक एक विशाल शहरी विस्तार परियोजना की घोषणा की है।

स्थान	प्रस्तावित Mumbai 3.0 शहरी केंद्र के लिए रायगढ़ जिला प्रस्तावित स्थान है।
तथ्य	यह परियोजना 323.44 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करती है।
संस्था	MMRDA (Mumbai Metropolitan Region Development Authority) इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है।
तथ्य	इस परियोजना को Brookfield से \$12 बिलियन के निवेश का समर्थन प्राप्त है।

मेन्स प्रश्न भारत के महानगरों में तीव्र शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के दबाव को प्रबंधित करने के लिए उपग्रह शहरी केंद्रों (सेटेलाइट अर्बन सेंटर्स) के निर्माण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सिटी गैस वितरण संस्थाओं को सब्सिडी प्रदान करके घरेलू पाइपड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शनों की प्रक्रिया को गति देनेके लिए एक योजना की घोषणा की है

चर्चा में क्यों पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सिटी गैस वितरण संस्थाओं को सब्सिडी प्रदान करके घरेलू पाइपड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शनों की प्रक्रिया को गति देनेके लिए एक योजना की घोषणा की है।

- तथ्य** वर्तमान में भारत में 1.74 करोड़ घरेलू पाइपड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन हैं।
- तथ्य** नई योजना का उद्देश्य गैस वितरण संस्थाओं के लिए पेबैक अवधि (payback period) को 10 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करना है।
- विज्ञान** PNG, घरेलू उपयोग के लिए LPG सिलेंडरों की तुलना में एक स्वच्छ और सुरक्षित विकल्प है।

मेन्स प्रश्न भारत के स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण में पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (PNG) बुनियादी ढांचे के विस्तार के महत्व और ग्रामीण-शहरी ऊर्जा समानता पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए।

अमेरिका, इजरायल और ईरान के मध्य भू-राजनीतिक तनाव ने तेल और गैस की आपूर्ति को बाधित कर दिया

चर्चा में क्यों अमेरिका, इजरायल और ईरान के मध्य भू-राजनीतिक तनाव ने तेल और गैस की आपूर्ति को बाधित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की कमी को पूरा करनेके लिए वैश्विक स्तर पर कोयले की खपत में भारी वृद्धि हुई है।

- तथ्य** मांग में उछाल के बावजूद कोयले की कीमतें तेल की तुलना में सस्ती बनी हुई हैं।
- स्थान** Thungela Resources दक्षिण अफ्रीका स्थित एक थर्मल कोयला उत्पादक है।
- तथ्य** प्रमुख कोयला निर्यातकों में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और रूस शामिल हैं।

मेन्स प्रश्न मध्य पूर्व में भू राजनीतिक संघर्षों का वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

कोटक महिंद्रा बैंक के 5.47% पांच साल के बॉन्ड के लिए \$2.1 billion की भारी डिमांड

चर्चा में क्यों कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने प्रथम ऋण निर्गम (debt issuance) के माध्यम से सफलतापूर्वक \$2.1 बिलियन जुटाए हैं, जो भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्डों के प्रति वैश्विक निवेशकों की प्रबल रुचि को रेखांकित करता है।

- तथ्य** कोटक महिंद्रा बैंक के पांच-वर्षीय बॉन्ड की कीमत 5.47% निर्धारित की गई।
- संस्था** S&P (Standard & Poor's) ने बॉन्ड के लिए 'BBB' रेटिंग प्रदान की।
- संस्था** SEBI वह नियामक संस्था है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड वितरण पर एक परामर्श पत्र (consultation paper) तैयार कर रही है।
- तथ्य** एक बेसिस पॉइंट (bps) 0.01 प्रतिशत बिंदु के बराबर होता है।

मेन्स प्रश्न भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा करने के महत्व और खुदरा भागीदारी बढ़ाने में विनियामक सुधारों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

कर्नाटक सरकार ने 'कोड ऑन वेजेज, 2019' के अनुरूप मई 2026 के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी संशोधनों की समीक्षा करने हेतु एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है

चर्चा में क्यों कर्नाटक सरकार ने 'कोड ऑन वेजेज, 2019' के अनुरूप मई 2026 के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी संशोधनों की समीक्षा करने हेतु एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है।

- अधि नियम** Code on Wages, 2019: न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी और बोनस को सरल और सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से एक केंद्रीय विधान।
- तथ्य** न्यूनतम मजदूरी संशोधन के लिए अधिसूचना 22 मई, 2026 के लिए निर्धारित है।
- संस्था** कैबिनेट उप-समिति (Cabinet Sub-committee): मंत्रियों का एक छोटा समूह जिसे अंतिम कैबिनेट निर्णय से पहले विशिष्ट मुद्दों की विस्तार से जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

मेन्स प्रश्न भारत में औद्योगिक विकास और श्रम कल्याण पर न्यूनतम मजदूरी संशोधनों के प्रभाव की चर्चा कीजिए। श्रम संहिता, 2019 इन परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए किस प्रकार लक्षित है? विश्लेषण कीजिए।

VB-G RAM G Act से ग्रामीण श्रमिकों की नौकरियां गई, रोजगार में 40% से ज्यादा की गिरावट

चर्चा में क्यों VB-G RAM जी. अधिनियम के कारण ग्रामीण रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जो जुलाई 2025 की तुलना में 40% से अधिक कम हो गई है।

तथ्य	VB-G RAM G Act के तहत रोजगार सृजन में जुलाई 2025 की तुलना में 40% से अधिक की गिरावट आई है।
तथ्य	जुलाई 2026 के लिए अनुमानित रोजगार लगभग 9 करोड़ व्यक्ति-दिन है।
संस्था	VB-G RAM G Act केंद्र सरकार का रोजगार गारंटी कानून है।

मेन्स प्रश्न रोजगार गारंटी योजनाओं में विधायी परिवर्तनों का ग्रामीण आजीविका और कृषि कार्यबल की सामाजिक-आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

2

चीन ने पहली बार ज़मीन पर Zhuque-3 रॉकेट स्टेज को रिकवर किया

चर्चा में क्यों चीन ने पहली बार 'झुके-3' (Zhuque-3) रॉकेट के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक भूमि पर पुनः प्राप्त किया है, जो पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

विज्ञान	Zhuque-3: निजी चीनी फर्म LandSpace द्वारा विकसित एक रॉकेट।
विज्ञान	पुनः प्रयोज्य रॉकेट (Reusable rockets): अंतरिक्ष यान जिन्हें लागत कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए कई बार प्रक्षेपित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
तथ्य	चीन का दूसरा रिकवरी प्रयास: पहला जुलाई में एक समुद्री प्लेटफॉर्म की रिकवरी थी।

मेन्स प्रश्न अंतरिक्ष अन्वेषण की लागत को कम करने में पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक के महत्व और वैश्विक अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

NASA ने चांद पर SpaceX Falcon 9 के क्रेटर की नई तस्वीरें जारी कीं

चर्चा में क्यों NASA ने चंद्रमा पर SpaceX Falcon 9 के प्रभाव से बने गड्ढे (इम्पैक्ट क्रेटर) की उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली छवियां जारी की हैं, जो चंद्र सतह के अवलोकन और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग में हुई प्रगति को रेखांकित करती हैं।

विज्ञान	Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO): चंद्रमा की सतह का मानचित्रण करने के लिए डिज़ाइन किया गया NASA का एक अंतरिक्ष यान।
तथ्य	SpaceX Falcon 9 के प्रभाव से बने गड्ढे (impact crater) की चौड़ाई 60 फीट और गहराई 10 फीट से कम है।
विज्ञान	KPLO: Korea Pathfinder Lunar Orbiter, जिसका उपयोग कोरियाई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रारंभिक चित्र साझा करने के लिए किया जाता है।

मेन्स प्रश्न चंद्र अन्वेषण के महत्व और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं चंद्र सतह के मानचित्रण को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

3

केरल की एयर क्वालिटी दक्षिण भारत में सबसे खराब, स्टडी में 25 शहर PM10 स्टैंडर्ड में फेल

चर्चा में क्यों CSTEP के एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि दक्षिण भारत में वायु प्रदूषण में केरल का स्थानीय योगदान सर्वाधिक है, जहाँ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अंतर्गत 25 शहर PM10 मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं।

तथ्य	दक्षिण भारत में वायु प्रदूषण में केरल का स्थानीय योगदान 65% है।
तथ्य	NCAP के तहत दक्षिण भारत के 25 शहरों को गैर-प्राप्ति (non-attainment) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
संस्था	CSTEP (Council on Sustainable Ecological Systems and Technologies) ने इस अध्ययन को संचालित किया।
योजना	NCAP (National Clean Air Programme) उन शहरों को लक्षित करता है जहाँ PM10 और PM2.5 की सांद्रता निर्धारित सीमाओं से अधिक है।

मेन्स प्रश्न भारत में 'एयरशेड' (वायुमंडल क्षेत्र) स्तर पर वायु गुणवत्ता के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण नियंत्रण हेतु अंतर-राज्यीय सहयोग को बेहतर बनाने के उपाय सुझाइए। चर्चा कीजिए।

मरीन वर्म्स प्लास्टिक जैसे पदार्थों को तोड़ रहे हैं, नेचुरल क्लीनअप की ओर संकेत

चर्चा में क्यों शोधकर्ताओं ने खोज की है कि *Olavius algarvensis* जैसे समुद्री कृमि (marine worms) में पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्केनोएट्स (PHAs) को विघटित करने वाले एंजाइम मौजूद होते हैं, जो बायोप्लास्टिक्स के प्राकृतिक जैव-अपघटन (biodegradation) के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

विज्ञान	Olavius algarvensis: एक समुद्री कृमि (marine worm) की प्रजाति जो polyhydroxyalkanoates (PHAs) को विघटित करने में सक्षम है।
विज्ञान	PHAs: सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित प्राकृतिक पॉलिमर जो बायोप्लास्टिक्स के लिए आधार के रूप में कार्य करते हैं।
संस्था	मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मरीन माइक्रोबायोलॉजी: अध्ययन में शामिल शोध निकाय।

मेन्स प्रश्न वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट के समाधान में जैविक निम्नीकरण (biological biodegradation) की क्षमता और सतत अपशिष्ट प्रबंधन में जैव प्लास्टिक (bioplastics) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

Great Pacific Garbage Patch: 79 Thousand टन प्लास्टिक से समुद्री जीवों को खतरा

चर्चा में क्यों एक अध्ययन 'ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच' के विशाल विस्तार और समुद्री जैव विविधता के लिए माइक्रोप्लास्टिक्स एवं मछली पकड़ने वाले जालों से उत्पन्न गंभीर खतरे पर प्रकाश डालता है।

तथ्य	Great Pacific Garbage Patch 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
तथ्य	माइक्रोप्लास्टिक्स कुल टुकड़ों का 94% हिस्सा बनाते हैं, लेकिन कुल द्रव्यमान का केवल 8% हिस्सा हैं।
तथ्य	मछली पकड़ने वाले जाल (Fishing nets) इस पैच के कुल द्रव्यमान के कम से कम 46% का हिस्सा हैं।
संस्था	NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) समुद्री मलबे और महासागर के स्वास्थ्य की निगरानी करता है।

मेन्स प्रश्न समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण के पारिस्थितिक प्रभावों की चर्चा कीजिए और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता रणनीतियों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए।

आपदा प्रबंधन

1

ओडिशा CM ने 9.4 लाख प्रभावित लोगों के लिए ₹1,000-Crore का बाढ़ राहत पैकेज घोषित किया

चर्चा में क्यों ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित 9.4 लाख लोगों को राहत प्रदान करने के लिए ₹1,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है।

तथ्य	जून से अब तक ओडिशा में 1,100 mm वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत से 34% अधिक है।
तथ्य	राहत पैकेज 6 जिलों को कवर करता है और 9.4 लाख प्रभावित लोगों को लक्षित करता है।
तथ्य	राहत उपायों में किसानों, शिल्पकारों और बुनकरों के लिए सब्सिडी शामिल है।

मेन्स प्रश्न ओडिशा जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा ग्रामीण आजीविका की सुदृढ़ता बढ़ाने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

आंतरिक सुरक्षा

1

पाकिस्तानी मौलाना का दावा, हाफिज सईद ने कश्मीर भेजे 10,000 आतंकी

चर्चा में क्यों एक पाकिस्तानी धर्मगुरु द्वारा हाफिज सईद द्वारा कश्मीर में 10,000 आतंकवादियों को भेजने के दावे ने क्षेत्रीय आतंकवाद में लश्कर-ए-तैबा (LeT) की भूमिका पर पुनः जांच और scrutiny को जन्म दिया है।

तथ्य	Lashkar-e-Taiba (LeT) पाकिस्तान स्थित एक उग्रवादी समूह है।
स्थान	पहलगाम कश्मीर क्षेत्र में स्थित एक स्थान है।
तथ्य	हाफिज सईद Lashkar-e-Taiba संगठन के संस्थापक हैं।

मेन्स प्रश्न भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सीमा पार से होने वाले आतंकवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह टेलीग्राम पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + विडिओ · हर रविवार साप्ताहिक · हिंदी और अंग्रेज़ी · मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh · satyadheesh.in/upsc/reports

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।